भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बढ़ी

2 से 4 जून तक नई दिल्ली में जारी है वार्ता

नई दिल्ली, 2 जून. भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों ने समझौते

मार्केट एक्सेस और निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर

के पहले चरण के अधिकांश प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप दे दिया है। अब वार्ता का केंद्र समझौते के कानूनी मसौदे को तैयार करना और शेष मुद्दों पर सहमति बनाना है।

नई दिल्ली में 2 से 4 जून तक चल रही वार्ता में भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्ष अंतरिम व्यापार समझौते के अंतिम स्वरूप पर गहन चर्चा कर रहे हैं।

प्रस्तावित समझौते के तहत बाजार पहुंच (मार्केट एक्सेस), गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, व्यापार सुगमता बढ़ाना और निवेश प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों देश इन विषयों को बड़े और व्यापक बीटीए के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं।

> यह समझौता दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई दे सकता है। अमेरिका वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। ऐसे में यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलने के साथ निवेश और आर्थिक सहयोग को भी मजबूती देगा। वार्ता के सफल निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे, जिससे दोनों देशों के उद्योगों, निवेशकों और कारोबारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। ट्रेड डील पर सहमति बढ़ी

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ राहत, भारत को अवसर

भारत के कृषि और विनिर्माण क्षेत्र को मिल सकता है अप्रत्यक्ष फायदा

नई दिल्ली, 2 जून अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि और औद्योगिक उपकरणों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर, बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट और

कृषि और औद्योगिक उपकरणों पर टैरिफ 15%
अमेरिकी स्टील-एल्युमीनियम इस्तेमाल करने पर 10%

अन्य औद्योगिक मशीनरी पर टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

यह व्यवस्था दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी। व्हाइट हाउस का

कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी किसानों और उद्योगों की लागत कम करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस फैसले का असर भारत सहित कई व्यापारिक साझेदार देशों पर भी पड़ सकता है। नई नीति के तहत उन विदेशी निर्माताओं को अतिरिक्त रियायत मिलेगी जो अपने उपकरणों में वजन के हिसाब से कम से कम 85 प्रतिशत अमेरिकी स्टील या एल्युमीनियम का उपयोग करेंगे। ऐसे उत्पादों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए स्टील और एल्युमीनियम का उत्पादन और प्रसंस्करण अमेरिका में ही होना आवश्यक होगा।

टैरिफ में कमी से अमेरिकी बाजार में कृषि और औद्योगिक उपकरणों की कीमतें कम हो सकती हैं। इसका अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय खरीदारों को भी मिल सकता है, जो आधुनिक मशीनरी और तकनीक आयात करते हैं।

> यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। दोनों देश बाजार पहुंच, सीमा शुल्क, गैर-टैरिफ बाधाओं और निवेश प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में टैरिफ कटौती को व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

शेयर बाजार में तेजी

आईटी शेयर चमके

मुंबई, 2 जून स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को भारी उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों को निवेशकों के समर्थन से प्रमुख सूचकांक में तेजी दर्ज की गयी।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 382.50 अंक (0.52 प्रतिशत) चढ़ कर 74,649.84 पर और एनएसई निफ्टी-50 100.95 अंक (0.43 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 23,483.55 पर रहा।

बीएसई का 30 संसेक्स सुबह बड़ी गिरावट के साथ 73,945.20 पर खुला और कारोबार के दौरान ऊपर में 74,862.19 तथा नीचे में 73,815.12 तक गिरने के बाद अंत में 74,649.84 पर बंद हुआ। जबकि कल सेंसेक्स 74,267.34 पर बंद हुआ था।

सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर लाभ में और दस गिरावट में बंद हुये। लाभ में रहे प्रमुख शेयरों में आईटी कंपनी टीसीएस 6.53 प्रतिशत , इन्फोसिस 5.66 प्रतिशत, एचसीएल टेक 4.08 प्रतिशत, टेक महिंद्रा 1.75 प्रतिशत और अडानी पोर्ट का शेयर 1.75 प्रतिशत लाभ में रहा।

चीन के नए टेक कानून से बढ़ी चिंता

विदेशी अधिग्रहण और टेक डील्स में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा

नई दिल्ली, 2 जून। चीन ने अपनी तकनीकी बढ़त और रणनीतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए नया कानून लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत देश की कंपनियों, तकनीक, डेटा और विशेषज्ञों के विदेश जाने पर सख्त नियंत्रण रहेगा।

चीन की कैबिनेट द्वारा मंजूर

1 जुलाई से लागू होंगे कड़े नियम

किए गए ये नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। माना जा रहा है कि इस कदम का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ-साथ भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माण

क्षेत्र पर भी पड़ सकता है नए नियमों के अनुसार कोई भी चीनी कंपनी बिना सरकारी अनुमति के उन्नत तकनीक, संवेदनशील डेटा या विशेषज्ञों को विदेशी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध नहीं करा सकेगी। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सरकार की निगरानी और मंजूरी अनिवार्य होगी।

> चीन ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। बीजिंग का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए तकनीकी ज्ञान और प्रतिभा के अनियंत्रित प्रवाह को रोकना आवश्यक है।

खटवानी मोटर्स में नई जेएसडब्ल्यू एमजी मेजेस्टर का शुभारंभ

नवभारत, जबलपुर। खटवानी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में अत्याधुनिक फीचर्स वाली नई जेएसडब्ल्यू एमजी मेजेस्टर का शुभारंभ हुआ। वाहन का अनावरण चेयरमैन रामचंद्र खटवानी, एमडी रोबिन खटवानी, सीईओ शिखा खटवानी, सीईओ ऋग्वेद खटवानी एवं महाप्रबंधक आलोक चौरसिया ने किया। ?40.99 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली यह कार भारत की पहली डी-प्लस सेगमेंट एसयूवी है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ऊंची और लंबी है। यह गाड़ी आकर्षक एक्सटीरियर, विशाल रोड प्रेजेंस, आधुनिक तकनीक और लग्ज़री इंटीरियर के साथ नया मानक बनाएगी। लॉन्च पर टेस्ट ड्राइव की विशेष व्यवस्था भी रही।

दमदार फीचर्स और कनेक्टिविटी

एमजी मेजेस्टर में 2.0 लीटर

ट्विन टर्बो इंजन, एडवांस एम-हब 4×4 सिस्टम, मल्टीपल टेरेन मोड्स और प्रीमियम एम-लाउंज इंटीरियर है। इसमें पैनोरमिक गैलेक्सी व्यू रूफ, वेंटिलेटेड व मसाज सीट्स तथा 12-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स हैं। साथ ही यह वाहन 75 से अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले व एंड्रॉइड ऑटो, डिजिटल कॉकपिट और स्मार्ट कनेक्टिविटी तकनीक से लैस है।

सुरक्षा तकनीक और पैकेज

सुरक्षा हेतु एमजी मेजेस्टर एडास लेवल-2 तकनीक से लैस है, जिसमें एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 360-डिग्री कैमरा और मल्टीपल एयरबैग्स जैसी सुविधाएं हैं। इसके साथ ग्राहकों को 3-3-3 ओनरशिप पैकेज के तहत 3 वर्ष की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, 3 वर्ष रोडसाइड असिस्टेंस व 3 लेबर-फ्री सर्विसेज मिलेगी।

मदर डेयरी लाई ईको-फ्रेंडली मिल्क पाउच

एक बार इस्तेमाल के बाद मिट्टी में धीरे-धीरे गल-पच जाएगा

नयी दिल्ली, 2 जून दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विकास की प्रमुख संस्था एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेयरी ने पहली बार पैकिंग के लिए एक ऐसा मिल्क पाउच प्रस्तुत किया है जो एक बार इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिल कर धीरे धीरे गल-पच जाएगा।

एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ मीनेश शाह ने मंगलवार को यहां कहा कि पर्यावरण और

पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते मदर डेयरी ने जैविक तरीके से गल-पच कर मिट्टी बन जाने वाले विशेष डीग्रेडेबल उत्पाद से तैयार पाउच का उपयोग करने का फैसला किया है। इसे मदर डेयरी के लोकप्रिय गाय के दूध की पैकिंग में इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर पांच जून को की जाएगी। इस डिग्रेडेबल पैकेजिंग में ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल किया गया है जो दूध की थैली को बायोअवेलेबल-वैक्स (जैविक मोम) में बदलने में सहायक बनाती है। उस बायोअवेलेबल वैसक्स को मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स सूक्ष्म टुकड़ों में विभाजित करके प्राकृतिक तत्वों में बदल देते हैं।

सोना 983 महंगा, चांदी 5,233 उछली

नई दिल्ली,2 जून। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिला। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव तथा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी के बाद निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे दोनों कीमती धातुओं में जोरदार तेजी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 983 रुपये की बढ़त के साथ 1,60,224 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा।

यूपीआई ने रचा डिजिटल भुगतान में इतिहास

मई 2026 में 23 .2 अरब लेन-देन के साथ यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 2 जून भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति को नई ऊंचाई देते हुए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने मई 2026 में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है।

29 .9 लाख करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मई महीने में यूपीआई

के माध्यम से 23.2 अरब से अधिक डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए। इन ट्रांजैक्शनों का कुल मूल्य 29.9 लाख करोड़ रुपये रहा, जो देश में डिजिटल भुगतान के तेजी से बढ़ते दायरे और उपभोक्ताओं के भरोसे को दर्शाता है।

आम लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा

एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 के दौरान यूपीआई ने कुल 23,201.93 मिलियन लेनदेन संसाधित किए। औसतन प्रतिदिन 73.78 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जबकि दैनिक भुगतान का औसत मूल्य 84,423 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि यूपीआई अब केवल एक भुगतान माध्यम नहीं, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। खुदरा खरीदारी, व्यापारी भुगतान और व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन में यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक, डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई पहली पसंद बन गया है। इसकी आसान प्रक्रिया, त्वरित भुगतान सुविधा और व्यापक स्वीकार्यता ने इसे आम लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया है।

समाचार विशेष

भाजपा बदल सकती है सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष!

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पूरी तरह बदलने वाली है. बीजेपी की यूपी इकाई में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है. यूपी बीजेपी का पुनर्गठन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है. यूपी बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. यूपी के बीजेपी संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव होने की संभावना है. संकेत मिल रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की क्षेत्रीय इकाइयों में पूरी तरह बदलाव किया जाएगा. इसके साथ राज्य में बीजेपी संगठन के शीर्ष नेतृत्व में भी करीब 50 फीसदी बदलाव देखने को मिलेगा.

नए पदाधिकारियों की लिस्ट तैयार- उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में फेरबदल को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व राज्य महासचिव (संगठन) धर्म पाल सिंह से गहन चर्चा की है. सूत्रों के अनुसार, पंकज चौधरी ने राज्य इकाई में बदलाव से संबंधित सारी जानकारी पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है. इस पर पार्टी जल्द ही अपनी औपचारिक मोहर लगा सकती है. यूपी बीजेपी इकाई में अध्यक्ष पंकज चौधरी और महासचिव धर्म पाल सिंह के अलावा 43 सदस्य हैं. इनमें 18 उपाध्यक्ष, सात राज्य महासचिव, 16 सचिव, एक कोषाध्यक्ष और एक सह-कोषाध्यक्ष शामिल है. इसी तरह पार्टी की छह क्षेत्रीय इकाइयां हैं. इनमें एक-एक क्षेत्रीय अध्यक्ष और करीब 16-16 सदस्य हैं.

बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना-उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने की तैयारी में है. इनमें से कुछ को राज्य इकाई में शामिल किया जा सकता है. इसके बाद नए क्षेत्रीय अध्यक्ष अपनी-अपनी टीमों का गठन करेंगे.

> **मोर्चों के भी बनेंगे नए अध्यक्ष**
>
> बीजेपी अपने सात मोर्चों, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के नए अध्यक्षों की घोषणा भी कर सकती है. ये मोर्चे उन निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के प्रचार अभियान में लगाए जाते हैं, जहां इनसे संबंधित मतदाता वर्ग की संख्या अधिक है. यूपी बीजेपी के पुनर्गठन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है.

अन्नामलाई के बयान ने बढ़ाई भाजपा की धड़कनें

नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज

चेन्नई. तमिलनाडु में सरकार बदल गई है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल अभी थमी नहीं है. इन दिनों बीजेपी के युवा नेता के अन्नामलाई काफी सुर्खियों में हैं. राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि अन्नामलाई भाजपा से अलग होकर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं.

कोयम्बटूर शहर में कई जगह उनके फोटो के साथ 'फियरलेस माइंड्स गेव नो लिमिट्स' का पोस्टर लगा है. इसके बाद से चर्चा चल रही है कि वे एक अलग राजनीतिक मंच बनाने जैसी कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल करने की तैयारी कर रहे हैं. विपक्ष द्वारा भी मामले पर लगातार बयान दिया जा रहा है.

4 जून को अन्नामलाई के जन्मदिन से पहले प्रमुख सडक़ों और सार्वजनिक स्थानों पर 'हमारे नेता, आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए' जैसे नारों वाले ये पोस्टर लगाए गए थे. इन पोस्टरों के लगने से तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है. खासकर, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व के कुछ वर्गों के बीच बढ़ते मतभेदों की खबरों के बीच.

दिल्ली दौरे से चर्चा तेज- दिल्ली रवाना होने से पहले अन्नामलाई से जब मीडिया ने एक नई पार्टी शुरू करने की अटकलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, इंतजार करें. हम दो दिनों में बैठकर बात करेंगे. उनकी इस टिप्पणी ने पार्टी छोडऩे की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. हालांकि, भाजपा नेताओं ने किसी भी विभाजन की अटकलों को खारिज कर दिया है, और उनका कहना है.

> **ये है विवाद**
>
> सूत्रों के अनुसार, विधानसभा चुनाव के दौरान अन्नामलाई क्चछ्वक्क और ्रद्बड्डरूय के गठबंधन से खुश नहीं थे. चुनाव के दौरान वह खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे. उनके समर्थकों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी उम्मीद के मुताबिक उन्हें कोई भूमिका भी नहीं मिली. इससे भी उनके खेमे में नाराजगी बढ़ गई थी. इसके अलावा, कक्षा नौ के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति को आगे बढ़ाने के केंद्र के फैसले की उनकी हालिया आलोचना ने भी राजनीतिक बहस छेड़ दी और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों को लेकर नई अफवाहें पैदा कर दीं.

विशेष | नितिन नवीन ने दिया जीत का मंत्र

11 हजार बूथों पर भाजपा का चक्रव्यूह

देहरादून. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने उत्तराखंड प्रवास में संगठन को मजबूत करने की कवायद अवरोही क्रम अर्थात संगठन की ऊपरी इकाई से निचले क्रम में शुरू की. इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि प्रदेश कोर कमेटी में बनी कार्ययोजना को अंतिम इकाई तक पहुंचाकर उसका धरातल पर पालन कराया जा सके.

सबसे पहले कोर कमेटी के साथ बैठक में उन्होंने अपनी इसी योजना को मूर्तरूप दिया. भाजपा के 16 रणनीतिकारों के साथ हुई चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड के 11 हजार से अधिक बूथ अब भाजपा की चुनावी राजनीति के सबसे बड़े रणक्षेत्र बनेंगे.

नितिन नवीन ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को सीधे बूथ केंद्रित माडल पर खड़ा करने का प्लान तैयार किया. दरअसल भाजपा नेतृत्व का मानना है कि अब चुनाव अब सीधे बूथ से तय होते हैं. यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के बाद बूथ रचना को मजबूत करने पर सबसे अधिक जोर दिया. इसके लिए उन्होंने संगठन को पूरा प्लान समझाया. कहा, भाजपा की रणनीति का पहला चरण बूथों की समीक्षा से शुरू होगा. जिन बूथों पर पार्टी पिछली बार कमजोर रही, कम अंतर से हारी या जहां संगठन निष्क्रिय दिखा, वहां विशेष फोकस किया जाएगा.

हर बूथ अलग चुनावी इकाई - पार्टी हर बूथ को अलग चुनावी इकाई मानकर उसका राजनीतिक प्रोफाइल तैयार करेगी. किस बूथ पर किस जातीय, सामाजिक या क्षेत्रीय समीकरण का प्रभाव है, कौन से स्थानीय मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं और विपक्ष की पकड़ कहां मजबूत है, इसका विस्तृत आकलन किया जाएगा.

प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा का सर्वे शुरू

शिमला. हिमाचल प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भले ही अभी समय हो लेकिन प्रदेश की राजनीति में अंदरखाते हलचल बढ़ने लगी है. विपक्षी दल भाजपा ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया समय से पहले शुरू कर दी है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों व्यापक स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है, इसके माध्यम से संभावित उम्मीदवारों को लेकर जनता की राय जानी जा रही है.

पार्टी से जुड़े लोगों, आम मतदाताओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है. कॉल के दौरान न केवल संभावित दावेदारों के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है, बल्कि क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, मौजूदा कांग्रेस सरकार के कामकाज और भाजपा नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि सर्वे में टिकट के संभावित दावेदारों के नाम लेकर लोगों से उनकी प्राथमिकता पूछी जा रही है. कॉल करने वाली एजेंसी लोगों से एक से चार तक रैंकिंग देने को कह रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस नेता की क्षेत्र में सबसे अधिक स्वीकार्यता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस बार टिकट वितरण में स्थानीय समीकरणों और जनता की राय को अधिक महत्व देने की रणनीति पर काम कर रही है. पिछले चुनावों में कई सीटों पर टिकट आवंटन को लेकर असंतोष सामने आया था, जिसका असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ा.

कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल भांपने की कोशिश

भाजपा का यह सर्वे केवल टिकट चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से पार्टी प्रदेश में कांग्रेस सरकार के प्रति जनता का रुझान भी समझना चाहती है. फोन कॉल में लोगों से सरकार की योजनाओं, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी और विकास कार्यों को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं. इससे भाजपा आगामी चुनावी मुद्दों की रूपरेखा तैयार करने में जुटी दिखाई दे रही है. पार्टी यह जानना चाहती है कि किन मुद्दों को लेकर जनता में सबसे ज्यादा नाराजगी है और किन क्षेत्रों में संगठन को अधिक मेहनत करने की जरूरत है.